

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 60 ● अंक 18 ● भोपाल ● 16-28 फरवरी, 2017 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

पर्यटन, परिवहन, आईटी और उद्यानिकी में सहकारी फेडरेशन बनाने पर विचार होगा

राज्य मंत्री श्री सारंग "कौशल उन्नयन और सहकारिता" के राज्य-स्तरीय सम्मेलन में



भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि पर्यटन, आईटी, परिवहन और उद्यानिकी में सहकारिता के जरिये बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिये सहकारी समितियाँ बनाई जायेगी और इसका फेडरेशन बनाने के लिये सरकार विचार करेगी। श्री सारंग "कौशल उन्नयन एवं सहकारिता" पर म.प्र. राज्य सहकारी संघ भोपाल द्वारा राष्ट्रीय सहकारी संघ के सहयोग से आयोजित राज्य-स्तरीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन की अध्यक्षता श्री अरुणसिंह तोमर ने की।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता आंदोलन से महिलाओं का जुड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वे इस आंदोलन की मुख्य धुरी हैं। उनके जरिये ही परिवार में संस्कार आते हैं, जिनका विस्तार देश और समाज में होता है। श्री सारंग ने कहा कि अगर सहकारिता से महिलाएँ बड़े पैमाने पर जुड़ेंगी तो निश्चित ही हम इस आंदोलन के जरिये उत्थान और सर्वांगीण विकास का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि सहकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक है। पिछले 10 साल में इसका विस्तार हुआ है। समन्वय और सदभाव की नीति पर चलते हुए प्रदेश में सहकार की भावना मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि

यह जरूरी है कि हम इसे नीचे तक ले जायें और इसे वंचित वर्ग के उत्थान का माध्यम बनायें। उन्होंने कौशल उन्नयन की पहल को जरूरी बताया।

सहकारी प्रबंध संस्थान के अध्यक्ष श्री अरुण सिंह तोमर ने कहा कि आज प्रदेश सहकारिता के मामले में पूरे देश में अग्रणी राज्य है। उन्होंने सहकारिता में नई संभावनाओं को तलाशने और उन्हें क्रियान्वित करने पर जोर दिया तथा सम्मानित संस्थाओं ने लाभार्जन कर मार्गदर्शन किया है उन्होंने सौर उर्जा की सहकारी संस्थाओं के गठन की अपेक्षा की। इस मौके पर राज्य सहकारी संघ की वेबसाइट तथा व प्रदेश की सहकारी उपलब्धियों पर आधारित ब्रोसर का लोकार्पण व विमोचन

भी किया गया।

सर्वप्रथम म.प्र. राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने सम्मेलन की रूपरेखा तथा महत्व, सम्मेलन के तकनीकी सत्र में हुवे विचार मंथन तथा कौशल उन्नयन में राज्य सहकारी संघ की प्रगति पर प्रकाश डाला।

सम्मेलन में सहकारिता के क्षेत्र में नवाचार करने और उत्कृष्ट काम करने वाली संस्थाओं को प्रमुख रूप से श्री रतन यादव, अध्यक्ष, उपभोक्ता संघ, श्री जीवन मैथिल, श्री विवेक श्रोती, श्री धर्मेन्द्र अहिरवार, अपर आयुक्त श्री जे.पी. गुप्ता, श्री अजय दीक्षित, श्री अरुण माथुर तथा अन्य सहकारिता विभाग के अधिकारी



गण एवं श्रीमती आशा सेंगर सहित गणमान्य अतिथिगण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री निरंजन कसारा, ने किया तथा आभार व्यक्त श्री अरुण जोशी ने व्यक्त किया।

कौशल उन्नयन पर विषय-विशेषज्ञ श्री नीलमेघ चतुर्वेदी, श्री सुधीर जैन और श्री सुरेन्द्र कुमार ने सहकारी संस्थाओं के कौशल उन्नयन पर विचार व्यक्त किये।

राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन

उपलब्धियाँ हुई सम्मानित

विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, आगरा



क्यों — विपणन संस्था आगरा ने कुछ अलग हटकर नवाचार के रूप में कार्य किया। इनके द्वारा पेट्रोल पंप का संचालन किया जा रहा है। इस कार्य से संस्था को वर्ष 2015-16 में 76 लाख का शुद्ध लाभ हुआ है।

किसने लिया सम्मान : श्री करणसिंह यादव, अध्यक्ष

जिला सहकारी संघ मर्यादित, उज्जैन



क्यों — जिला सहकारी संघ उज्जैन ने नवाचार के तहत 11 सहकारी संस्थाओं का पंजीयन कराया। हुनरमंद लोगों को प्रेरित किया तथा सहकारी प्रशिक्षण दिया। इनमें परिवहन, पर्यटन, सेवादायी, जैविक खाद तथा महिलाओं की गणवेश की सहकारी संस्थाएं शामिल हैं। जिला सहकारी संघ ने अपने स्तर से आवास व उपभोक्ता तथा अन्य के लिये प्रशिक्षण आयोजित कर 900 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया तथा सिंहस्थ के अवसर पर स्मारिका का प्रकाशन किया।

किसने लिया सम्मान : प्राधिकृत अधिकारी डा. मनोज जायसवाल, प्रबंधक श्री जगदीश प्रसाद बैरागी

वर्ल्ड विजन भोपाल



सुविधा साख सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल



क्यों — हुनर को रोजगार में तब्दील करने हेतु कुछ युवाओं ने प्लम्बरिंग, बढ़ाई, कारपेंटर तथा कारीगरी के कार्य को अंजाम देने हेतु सहकारिता को माध्यम चुना और नये युग के साथ आगे बढ़े और बढ़ते चले गये। सदस्य एक दूसरे से मोबाइल से एक प्लेटफार्म से जुड़े हैं। इस संस्था की एक यूनिक बात है कि संचालकों एवं सदस्यों की यूनिफार्म है। बैठकों में इन्हें पहनना अनिवार्य है।

किसने लिया सम्मान : श्री हेमलाल साहू, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्री आनंद तिवारी

प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था रेहटी, जिला सीहोर



क्यों — संस्था द्वारा औषधि निर्माण का कार्य स्थापना के बाद से निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। संस्था सीमित संसाधनों से औषधि निर्माण कर अपने अद्भुत, असाधारण कार्य से राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर वे प्रेरणास्पद कार्य कर रही है। यह कार्य एक नवाचार का रूप है। यहां विदेशों से भी विशेषज्ञ स्टडी टूर पर आने लगे हैं।

किसने लिया सम्मान : श्री सुरेश यादव, प्रबंधक

बीएचईई थ्रिप्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी, भोपाल

क्यों — भेल के कर्मचारियों ने 27 मार्च 1965 को अपनी साख की आवश्यकता की पूर्ति हेतु संस्था का पंजीयन कराया। आज भेल के 5175 कर्मचारी इसके सदस्य हैं। इनकी शत प्रतिशत वसूली है तथा सदस्यों से लोन राशि का 1 प्रतिशत राशि लेकर बीमा कराया जाता है। सोलर वाटर हीटर लगवाने का भी कार्य संस्था द्वारा किया जा रहा है। उत्कृष्ट थ्रिप्ट एवं क्रेडिट सहकारी संस्था के रूप में इनके कार्य अनुकरणीय रहे हैं।

क्यों — विश्व स्तर की यह स्वयं सेवी संस्था प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिये प्रयासरत है। संस्था ने भोपाल ही नहीं अन्य जिलों में महिलाओं की सहकारी संस्था का गठन कर महिला उत्थान के लिये कार्य किये हैं। भोपाल की प्रेरित महिला साख सहकारी संस्था इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रदेश के सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ बनाने में संस्था सतत प्रयासरत है।

किसने लिया सम्मान : श्रीमती थामस, संचालक

राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन : विषय विशेषज्ञों की राय

नवाचार से रोजगार

राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में उत्कृष्ट सहकारी संस्थाओं को सम्मानित किया गया। विषय विशेषज्ञों ने अपने-अपने विचार रखे। विचार मंथन में एक सुर में बात उभरी की नवाचार से जहां रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे वहीं सहकारिता सेवा का माध्यम बनकर सशक्ता से उभरेगी। सहकारिता की उज्ज्वल छवि देश में स्थापित होगी। तकनीकी सत्र का शुभारंभ श्री अरुणसिंह जी तोमर ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम पर प्रकाश प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने डाला।

**डा. सुरेन्द्र कुमार, संकाय सदस्य, सहकारी प्रबंध संस्थान भोपाल**

सोच, व्यवहार और कार्य में बदलाव/इनमें सोच और व्यवहार व्यक्ति निष्ठ है वहीं कार्य में बदलाव संस्थागत व्यक्ति के सोच में बदलाव आता है तो व्यवहार बदलता है। इससे संस्था के कार्यों में भी बदलाव आता है जिससे संस्थायें विकास की ओर अग्रसर होती हैं। संस्थायें विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। नवाचार से सदस्य रोजगार से जुड़ेंगे। श्री कुमार ने कहा कि नवाचार में प्लम्बरिंग, हार्टिकल्चर तथा सपेरा की सहकारी संस्थायें बनायीं जाय जिससे उन्हे रोजगार मिलेगा।

**श्री सुधीर जैन, महाप्रबंधक, एम.पी.कान.**

सहकारिता भी एम.बी.ए. है यहां सहयोग से प्रबंध किया जाता है। हम जो कार्य कर रहे हैं उसका उन्नयन कैसे हो। युवाओं को रोजगार के लिये प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन योजना प्रारंभ की गयी है। इसके तहत जो व्यक्ति जिसे क्षेत्र में कार्य कर रहा है उसे उसकी ट्रेनिंग दी जाय ताकि वह एक्सपर्ट हो। इसके साथ ही उन्हें डिग्री दी जाय। श्री जैन ने पाठ्यक्रमों में सुधार, ट्रेनिंग प्रोसेस के इम्पू तथा प्रशिक्षकों का उन्नयन की अपेक्षा की। साथ ही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तथा कार्य नये तरीके से करेंगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी।

**संजय मोहन भटनागर, उपायुक्त, सहकारिता**

नई तकनीकी से संवाद में गति, जवाबदेही तथा पारदर्शिता आयेगी। परिणाम स्वरूप सहकारिता जन सेवाएं का सशक्त माध्यम के रूप में उभरेगी। प्रदेश में ई-को.आपरेटिव्ह ई-पोर्टल बनाया गया है इसके तहत जी-2, जी-2-जी तथा जी-2-ई के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। इसके तहत आपके आवेदन की जानकारी एसएमएस के तहत भी प्राप्त होगी। प्रदेश में 33 लाख पैक्स संस्थाओं के किसान सदस्यों के खातों को आन लाइन किया जा चुका है। सहकारी न्यायालयों को भी आनलाइन किया जा रहा है। पेशी की जानकारी एसएमएस के जरिये तथा निर्णयों को भी डाउनलोड किया जा सकेगा। ई-फाइल ट्रेकिंग सिस्टम में भी प्रदेश का पहला विभाग है। विभाग में उपस्थिति को आधार कार्ड से जोड़कर बायोमेट्रिक किया गया है प्रदेश के ई-को.आपरेटिव्ह को पांच राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं।

**प्रेम द्विवेदी, उपायुक्त, सहकारिता**

सहकारी मंथन से उभरे बिंदुओं के आधार पर प्रदेश में नवाचार से संबंधित सहकारी संस्थाओं के गठन/पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी है। अन्य प्रदेशों में जिन क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं ने कामयाबी हासिल की है उन क्षेत्रों में प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। केरल के तर्ज पर प्रदेश में 19 पर्यटन, दिल्ली, लखनऊ की तर्ज पर ई-रिक्शा की 9, रहवासी संस्थायें भोपाल में 18 भंडारण, तथा केरल की जैविक खेती की महिला सहकारी संस्थाओं की तर्ज पर 55 संस्थायें गठित की जा चुकी हैं। मेडीकल क्षेत्र में भी विचार किया जा रहा है जिसके माध्यम से पैथोलॉजी व अन्य जांच की व्यवस्था होगी।

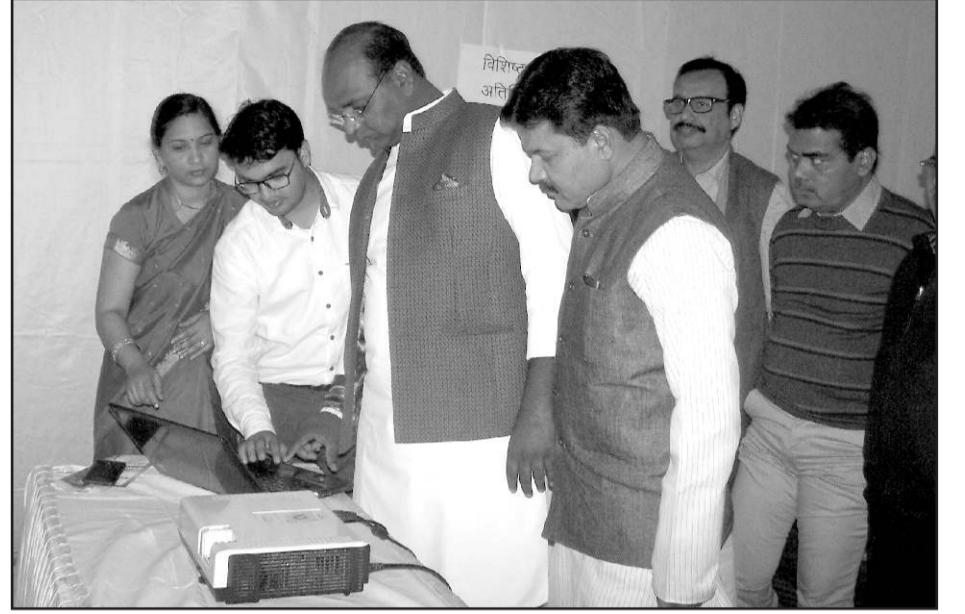
**नीलमेघ चतुर्वेदी, पत्रकार इंदौर**

प्रिंट मीडिया तथा सहकारिता की तुलना की तथा सहकारी क्षेत्र में प्रदेश में उठाये गये कदमों का जिक्र किया। बिल्डिंग मटेरियल की व्यवस्था एक अच्छा कदम है। क्रांतियों में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने प्रदेश में पाली हाउस तथा शहद उत्पादको की सहकारी संस्थाओं के गठन की आवश्यकता प्रतिपादित की।

राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन चित्रमय झलकियाँ



सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि माननीय श्री विश्वास सारंग राज्यमंत्री, सहकारिता (स्वतंत्र प्रभार)



सम्मेलन में राज्य सहकारी संघ की वेबसाइट का लोकार्पण करते हुए मुख्य अतिथि माननीय श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री, सहकारिता (स्वतंत्र प्रभार) समीप में हैं श्री अरुण सिंह तोमर, अध्यक्ष, सहकारी प्रबंध संस्थान, मोपाल



सम्मेलन का संचालन करते हुए म.प्र. राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन



सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधिगण



सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधिगण



सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधिगण

सबके साथ-सबका विकास नीति से प्रदेश-देश में अग्रणी

राज्य मंत्री श्री सारंग बैरसिया में सहकारिता सम्मेलन में



भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि सबके साथ-सबका विकास की नीति पर चलते हुए प्रदेश आज प्रगति के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। श्री सारंग बैरसिया में सहकारिता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि किसानों, गरीबों की चिन्ता मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी वर्गों की पंचायत कर उनके विकास और कल्याण के लिए रणनीति बनाई और उस पर अमल किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब बिजली, सड़क और पानी की उपलब्धता है।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। भ्रष्टाचार और काला धन खत्म करने

नोटबंदी का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया गया।

सहकारिता राज्य मंत्री श्री सारंग ने मिल-जुल कर विकास के पथ पर बढ़ने के लिये सहकारिता का रास्ता अपनाने और सहकारिता को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने सभी से सहकारिता की सदस्यता लेने, सहकारी बैंक में खाता खुलवाकर सदस्य बनने का किसानों और ग्रामीणों से आग्रह किया।

श्री सारंग स्थानीय मंडी में भोपाल सहकारी बैंक का काउण्टर बनाने, बैरसिया में एक किलोमीटर सड़क के डामरीकरण की घोषणा की। उन्होंने जिले की सभी सहकारी साख समितियों में पेयजल और शौचालय की सुविधा सहकारिता विभाग द्वारा सुलभ करवाने की बात कही।

सम्मेलन को विधायक श्री विष्णु खत्री, पूर्व विधायक श्री भक्तपाल

सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष श्री राजमल गुप्ता ने भी संबोधित किया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मनमोहन नागर, भोपाल जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष श्री मैथिल और श्री गोपाल सिंह मीणा सहित अन्य जन-प्रतिनिधि, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के संचालक और सदस्य मौजूद थे।

श्री सारंग द्वारा बैरसिया तहसील में पाँच गोदाम का लोकार्पण



भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने बैरसिया विकासखण्ड में नव-निर्मित एक करोड़ लागत के पाँच भवन का लोकार्पण किया। लोकार्पित भवनों में चार गोदाम और एक पंचायत भवन शामिल हैं। लोकार्पित भवनों में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना में ग्राम रायपुर की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के गोदाम, प्राथमिक सहकारी साख संस्था ललारिया का गोदाम, प्राथमिक सहकारी साख संस्था डुंगारिया का डुंगारिया में और कृषक सेवा सहकारी समिति बैरसिया का बैरसिया में 500 मीट्रिक टन का नव-निर्मित गोदाम है। प्रत्येक गोदाम भवन की निर्माण लागत 21 लाख 56 हजार है। श्री सारंग ने नरेला दामोदर ग्राम पंचायत भवन के नव-निर्मित भवन का भी लोकार्पण किया। भवन की लागत 13 लाख 63 हजार है।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने बैरसिया कृषि साख संस्था में कृषि मरम्मत केन्द्र की स्थापना करने की घोषणा की। श्री सारंग ने कहा कि बैरसिया कृषि साख संस्था परिसर में धर्मकाँटा स्थापित करने के साथ ही पीने के पानी और अन्य जरूरी सुविधाएँ उपलब्ध करवायी जायेगी। श्री सारंग ने ललारिया में 200 मीट्रिक टन का एक और गोदाम बनाने और श्री डुंगारिया सहकारी साख संस्था में तौल काँटा लगाने की घोषणा की। श्री सारंग ने भवन परिसर में बाउण्ड्री-वॉल बनाने और कुल्होर ग्राम में सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा खोलने की घोषणा भी की।

प्रदेश में प्रकृति आधारित खेती कर कृषि लागत में कमी करें

किसान-कल्याण मंत्री श्री बिसेन ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण का किया शुभारंभ



भोपाल। किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि राज्य सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया है। किसान प्रदेश में प्रकृति (आध्यात्मिक) कृषि कर खेती की लागत को कम कर सकते हैं। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाने की सलाह दी। किसान-कल्याण मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन भोपाल में शून्य बजट प्राकृतिक खेती पर आधारित तीन-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में पद्मश्री श्री सुभाष पालेकर भी मौजूद थे।

किसान-कल्याण मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि बिना कृषि के

औद्योगिक विकास संभव नहीं है। प्रायः सभी उद्योगों को उनकी जरूरत के प्रारंभिक उत्पाद की पूर्ति खेती से ही होती है। मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि देश की आजादी के बाद हम कृषि क्षेत्र में आत्म-निर्भर हुए हैं। मध्यप्रदेश में पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। किसान-कल्याण मंत्री ने कहा कि वर्ष 2003 में मध्यप्रदेश में गेहूँ का उत्पादन 24 लाख मीट्रिक टन हुआ करता था, जो वर्ष 2016 में 170 लाख मीट्रिक टन तक हो गया। वर्ष 2017 में गेहूँ का उत्पादन 200 लाख मीट्रिक टन तक होने का अनुमान लगाया गया है।

प्रदेश में दलहनी फसलों की चर्चा करते हुए श्री बिसेन ने कहा कि

पहले इसका रकबा 17 लाख हेक्टेयर हुआ करता था। अब यह 22 लाख हेक्टेयर तक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दलहनी फसलों की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जानी चाहिये। किसान-कल्याण मंत्री ने बताया कि जनवरी-2018 में भोपाल में राष्ट्रीय किसान मेला होगा। प्रदेश में सिंचाई का रकबा और अधिक बढ़ाये जाने पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसे बढ़ाकर 50 लाख हेक्टेयर तक पहुँचाया जायेगा। उन्होंने किसानों से अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण विकासखण्डों में स्थापित प्रयोगशाला में करवाये जाने का भी आग्रह किया।

सांसद श्री आलोक संजर ने कहा कि अंधाधुंध प्रतिस्पर्धा के कारण

हमने अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक इस्तेमाल किया है। इसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब यह सही समय है, जब हम प्रकृति आधारित खेती को अपनायें।

पद्मश्री श्री सुभाष पालेकर ने कहा कि खेती से जुड़ी %यादातर समस्याएँ वैश्विक हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, गाँव से हो रहा लगातार पलायन का सामना हम प्रकृति आधारित खेती से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हमें पर्याप्त संसाधन दिये हैं, जिनसे हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, किन्तु इनके जबरन दोहन से बचना होगा। उन्होंने कहा कि एक देशी गाय से 30 एकड़ क्षेत्र में

खेती की जा सकती है। पद्मश्री श्री पालेकर ने कहा कि स्वावलंबन पर आधारित अर्थ-व्यवस्था की अवधारणा से शहर का पैसा गाँव में आयेगा और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था मजबूत होगी।

किसान-कल्याण संचालक श्री मोहनलाल मीणा ने बताया कि 313 विकासखण्ड से किसान चयनित किये गये हैं। प्रशिक्षण शिविर में लगभग 1250 किसान और करीब 400 कृषि अधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद यह अधिकारी मास्टर-ट्रेनर के रूप में अपने क्षेत्र के किसानों को शून्य बजट प्रकृति (आध्यात्मिक) जानकारी देंगे। नर्मदा समग्र सेवा के श्री करण कौशिक ने भी संबोधित किया।

एसएमएस से राशन की जानकारी मिल रही मोबाइल पर

भोपाल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गठित निगरानी समिति के सदस्यों को राशन की जानकारी एस. एम.एस. से दी जा रही है। खाद्य आयुक्त श्री फैज अहमद किदवाई ने बताया कि समय पर पात्र हितग्राहियों को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ बिना परेशानी के राशन वितरण सुनिश्चित कराने में योगदान देने के लिए गठित ग्राम/दुकानवार निगरानी समितियों के सदस्यों को जानकारी एस.एम.एस. से दी जा रही है।

खाद्य आयुक्त ने बताया कि गोदाम से खाद्यान्न राशन दुकान पर पहुँचाने का एस.एम.एस. निगरानी समितियों के सदस्यों के मोबाइल पर किया जाता है। हितग्राहियों जिनके मोबाइल नम्बर की सीडिंग हो चुकी है उन्हें भी राशन उनकी दुकान पर पहुँचने की जानकारी का एस.एम.एस. किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी हितग्राहियों के मोबाइल नंबर की सीडिंग की जा रही है।

प्रदेश के 16 जिलों में 22 हजार 300 हेक्टेयर भूमि उद्यानिकी फसलों के लिये चयनित

भोपाल। प्रदेश में किसानों की आमदनी वर्ष 2022 तक प्रति हेक्टेयर दोगुनी करने के मकसद से नर्मदा नदी के दोनों तटों पर एक-एक किलोमीटर की पट्टी तक निजी भूमि पर फल पौध-रोपण की योजना 16 जिलों में शुरू की गयी है।

योजना के पहले साल वर्ष 2016-17 में 5000 हेक्टेयर में फलदार पौध-रोपण का कार्यक्रम तैयार किया गया है। प्रदेश के 16 जिलों में नर्मदा नदी के तट के दोनों ओर 24 हजार 341 किसान के खेतों में 22 हजार 300 हेक्टेयर भूमि का चयन उद्यानिकी फसलों के लिये किया गया है। जनवरी-2017 तक

5540 किसान ने वचन-पत्र भरकर 3062 हेक्टेयर में उच्च गुणवत्ता के फल पौधों का रोपण कर दिया है। इनमें आम, अमरूद, संतरा, मौसंबी, सीताफल, बेर, चीकू, अनार प्रमुख हैं। उद्यानिकी फसलों की इस

योजना में सभी वर्ग के हितग्राही को फल पौध-रोपण होने से पहले तीन वर्ष तक ली जाने वाली परम्परागत खाद्यान्न फसलों के एवज में 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।

पंचायत राज एवं स्वराज अधिनियम के प्रकरणों पर सुनवाई और निर्णय के लिए राज्य मंत्री श्री सारंग अधिकृत

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग को राज्य शासन ने पंचायत राज एवं स्वराज अधिनियम के तहत शासन को प्रस्तुत अपील पुनरीक्षण कर्मचारियों की सुनवाई एवं अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। अधिनियम के तहत अब जो भी प्रकरण शासन के समक्ष अपील में और सुनवाई के लिए आयेंगे वे प्रकरण राज्य मंत्री पंचायत ग्रामीण विकास के समक्ष प्रस्तुत होंगे। इन प्रकरणों में अंतिम निर्णय राज्य मंत्री स्तर पर ही लिया जायेगा। इस संबंध में आदेश जारी हो गया है।

शहरों के विकास के लिए अगले 5 साल में 86 हजार करोड़ रु. खर्च करेगी सरकार

मुख्यमंत्री श्री चौहान जबलपुर में नगर उदय अभियान के तीसरे चरण में हुए शामिल



भोपाल। नगर उदय अभियान के तहत समूचे प्रदेश में आयोजित यह कार्यक्रम दुनिया का पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें एक साथ एक दिन में एक समय पर 12 लाख 68 हजार 480 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर के गैरीसन मैदान में नगर उदय अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्पूर्ण प्रदेश का विकास ही राज्य सरकार का संकल्प है। इसे साकार करने के लिए आने वाले पाँच सालों में सरकार शहरी विकास के लिए 86 हजार करोड़ रूपए खर्च करेगी। उन्होंने विकास के लिए जनता को सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बताया। श्री चौहान ने कहा कि जनता न भटके, प्रशासन जनता के द्वार जाए और वाडों में बैठकर ही उनके विकास का खाका तैयार हो, इसलिए यह अभियान चलाया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य मध्यप्रदेश को समृद्ध, विकसित, वैभवशाली और गौरवशाली बनाकर सम्पूर्ण विश्व पटल पर स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश मेरा मंदिर है। जनता उसकी भगवान है और जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। इसके पहले मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 70 करोड़ से अधिक की लागत के विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं

लोकार्पण भी किया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 85 हजार 303 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया जिनमें जबलपुर नगरीय क्षेत्र के 67 हजार 86 हितग्राही शामिल थे।

शहर विकास के इंजन

मुख्यमंत्री ने शहरों को विकास के इंजन की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि शहर रोजगार के साधन हैं, विकास का दर्पण हैं। प्रदेश के 378 शहर में प्रदेश की 30 प्रतिशत आबादी निवास करती है। इस आबादी के प्रत्येक पात्र हितग्राही को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, यह हमारा उद्देश्य है।

एक मई से प्रदेशमें पालीथीन पर बैन

मुख्यमंत्री ने एक मई 2017 से सम्पूर्ण प्रदेश में पालीथीन पर बैन लगाने का ऐलान भी किया। उन्होंने पालीथीन को पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा कि इसके लिए पालीथीन का विकल्प भी कागज और कपड़े की थैलियों के रूप में तैयार किया जा रहा है जिनके अधिकाधिक उपयोग का आव्हान उन्होंने जनता से किया।

31 मार्च तक सभी शहरों को करेंगे खुले में शौच से मुक्त

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 मार्च तक प्रदेश के सभी शहरों को खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश के

60 शहर खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। यह एक बुराई है जिसके विरुद्ध हमारा स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। उन्होंने कार्यक्रम में

उपस्थित सभी नागरिकों को खुले में शौच न जाने और अपने शहर को स्वच्छ बनाने का संकल्प दिलाया। श्री चौहान ने कहा कि यह अभियान

मानसिकता में बदलाव लाने का अभियान है जो जनमानस की सहभागिता के बिना पूर्ण नहीं हो सकता।

कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र बनेगा प्रदेश का मॉडल

कुक्कुट-पालन प्रक्षेत्र में चार नये हैचर सेटर लगेगे, पशुपालन मंत्री श्री आर्य ने किया निरीक्षण



भोपाल। पशुपालन एवं मत्स्य-पालन मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने हथाईखेड़ा के कोकता स्थित शासकीय कुक्कुट-पालन प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया। श्री आर्य ने कड़कनाथ मुर्गी की विभिन्न प्रजाति, शेड आईसलैंड रेड, चैब्रो प्रजाति, हैचरी, ब्रूडर हाउस आदि का निरीक्षण किया।

मंत्री श्री आर्य ने कहा कि दुर्लभ प्रजाति कड़कनाथ दुनिया में सिर्फ मध्यप्रदेश में पायी जाती है। उन्होंने कहा कि भोपाल स्थित कुक्कुट-पालन प्रक्षेत्र को मॉडल के रूप में विकसित करना है। श्री आर्य ने पुराने

हैचर सेटर को हटाकर नई चार मशीनें स्थापित करने के निर्देश दिये। साथ ही हैचरी में शू-कवर मशीन लगाये जाने को कहा, जिससे इन्फेक्शन से बचाव हो सके। प्रक्षेत्र में शासकीय योजनाओं के लिये सभी जिले में मुर्गी और चूजों की सप्लाई की जाती है।

विस्तार के लिये बनेंगे

10 नए शेड

मंत्री श्री आर्य ने कहा कि विभिन्न प्रजातियों के कुक्कुट के विस्तार के लिये 10 नए शेड का निर्माण किया जाये। उन्होंने प्रक्षेत्र की बाउण्ड्री-वॉल ऊँची करने तथा सी.सी. टी.व्ही. कैमरे के लिये

प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने को कहा।

मंत्री श्री आर्य ने प्रक्षेत्र में लगी हुई डेयरी स्टेट की जमीन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यहाँ जमीन को समतल कर खरीफ और रबी की फसलों के लिये विकसित करने के निर्देश दिये। उप संचालक डॉ. डी.के. राय ने प्रक्षेत्र की जानकारी दी।

कृषि क्षेत्र को सिंचाई के लिये 10 घंटे

भोपाल। अधिकतम बिजली की माँग के बावजूद प्रदेश के कृषि क्षेत्र को सिंचाई के लिये 10 घंटे और घरेलू व्यावसायिक व औद्योगिक उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित की गई है। प्रदेश में वर्तमान रबी सीजन में 33 दिन बिजली की माँग 11 हजार मेगावाट से ऊपर बनी रही। सर्वोच्च स्तर से कम होने के बाद भी पिछले एक पखवाड़े से बिजली की माँग अभी भी 10 हजार 500 मेगावाट से ऊपर चल रही है जिसकी पूर्ति बराबर की जा रही है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 33 दिनों में से 20 दिनों तक लगातार 11 हजार मेगावाट या इससे ऊपर बिजली की माँग बनी रही।



मध्यप्रदेश शासन द्वारा किसान भाईयों से समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी के लिये नये सिरे से पंजीयन

पंजीयन अवधि दिनांक 14 जनवरी से 14 फरवरी 2017 तक।

किसान भाई कृपया ध्यान दें :

1. गेहूँ की खरीदी 27 मार्च 2017 से 31 मई 2017 तक की जायेगी।
2. रबी के पुराने किसान पंजीयन मान्य नहीं होंगे।
3. खरीदी केन्द्र पर कम्प्यूटर से नवीन पंजीकृत किसानों से ही खरीदी की जावेगी। अन्य से नहीं।
4. आधार नंबर और समग्र आई.डी. के साथ नवीन पंजीयन कराना अनिवार्य है।
5. किसानों का पंजीयन उपार्जन समिति द्वारा किया जावेगा।
6. किसान भाई सही जानकारी देवें, ताकि सत्यापन में परेशानी न हो।
7. पंजीयन पश्चात् कम्प्यूटर में दर्ज जानकारी देख लें और अगर कोई सुधार करना है, तो वहीं खरीदी केन्द्र पर करा लें।
8. पंजीयन के पश्चात् रसीद लेना न भूलें।



पंजीयन 14 फरवरी 2017 तक

**गेहूँ खरीदी
27 मार्च 2017 से**



नवीन पंजीयन हेतु निम्न अनिवार्य दस्तावेज साथ लायें

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. समग्र आई.डी. | 3. ऋण पुस्तिका |
| 2. आधार नंबर | 4. बैंक पासबुक। |

निम्न सावधानी बरतें

1. खाद्यान्न विक्रय के समय किसान पंजीयन की रसीद, ऋण पुस्तिका तथा बैंक पासबुक अवश्य लेकर आवें।
2. खरीदी केन्द्र पर एफ.ए.क्यू. गेहूँ ही लेकर आयें।
3. गेहूँ बेचने के बाद ऋण पुस्तिका में इसकी प्रविष्टि करायें।

किसानों को गेहूँ का उचित मूल्य दिलाने के लिये सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। रबी में समर्थन मूल्य पर गेहूँ बेचने के लिये शीघ्र नवीन पंजीयन करवा कर लाभ उठायें।

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कृषक हित में जारी।

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2017

D-80304/17